नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 063
दि. 05.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

बीएलओ पर बढ़ते दबाव ने सुप्रीम कोर्ट को किया चिंतित: पुनरीक्षण कार्य में राहत और अतिरिक्त स्टाफ लगाने का सख्त निर्देश

(जीएनएस)। नई दिल्ली की न्यायिक गलियारों में गुरुवार का दिन असाधारण रूप से महत्वपूर्ण रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ, पर पड़ रहे बढ़ते दबाव और लगातार सामने आ रही दिक्कतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। ऐसा बहुत कम होता है कि शीर्ष अदालत प्रशासनिक तंत्र के स्तर तक जाकर किसी समस्या की जड़ को संबोधित करे, लेकिन हालिया घटनाओं और बीएलओ की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अदालत ने साफ संकेत दिया कि अब इस प्रणाली में बिना देर किए सुधार करना अनिवार्य हो गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों और प्रशासन को कड़े शब्दों में कहा कि बीएलओ को अकेला न छोड़ा जाए, बल्कि तुरंत अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए ताकि उनके कंधों पर रखा गया बोझ संतुलित हो सके और किसी तरह की अनहोनी दोबारा न हो।

कोर्ट की यह टिप्पणी सिर्फ संवेदनशीलता से भरा बयान नहीं थी, बल्कि उन तमाम हालातों की ओर इशारा भी थी, जिनमें कई बीएलओ अपनी निजी परिस्थितियों के बावजूद लगातार फील्ड में काम करने को मजबूर हैं। अदालत ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि कोई बीएलओ निजी कारणों, स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियों या किसी अन्य उचित कारण से एसआईआर का कार्य करने में असमर्थ है, तो उसे प्रशासन द्वारा राहत दी जाए और उसके स्थान पर तुरंत किसी दूसरे कर्मचारी की तैनाती की जाए। यह भी कहा गया कि यदि किसी बीएलओ को उनकी स्थिति को देखते हुए राहत नहीं मिलती तो उन्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार होगा, और अदालत ऐसे मामलों को गंभीरता से सुनेगी।

हाल के दिनों में सामने आए हादसों ने भी अदालत का मन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ राज्यों में बीएलओ की मौत के बाद परिजनों को मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर परिवार बाद में भी मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है और उसे नियमों में बाधित नहीं किया जाएगा। ये सभी टिप्पणियाँ उन संवेदनशील वास्तविकताओं को सामने रखती हैं, जहाँ सरकारी मशीनरी के सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी कभी-कभी अपनी जान की कीमत देकर सरकारी आदेशों को निभाते हैं।

यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब तमिल अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी, टीवीके, की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी

कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए बीएलओ के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। टीवीके के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश में कई बीएलओ—जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हैं—के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने एक बेहद दर्दनाक उदाहरण साझा किया कि एक बीएलओ, जो शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी चाहता था, उसकी अनुमति न मिलने और निलंबन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। यह उदाहरण पूरे सिस्टम के भीतर छिपे उन खतरनाक दबावों को उजागर करता है, जिन्हें अक्सर फाइलों में नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन जिनका असर ज़मीन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर सीधे पड़ता है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही—कि निर्वाचन आयोग अकेले इस विशाल देश में एसआईआर का काम नहीं कर सकता। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अदालत के सामने साफ कहा कि बीएलओ पर अत्यधिक दबाव एक वास्तविक और गंभीर समस्या है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में जहाँ विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, वहां पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए सिर्फ एक महीने का समय क्यों दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक तैयारी और फील्ड कर्मचारियों की वास्तविक क्षमता के बीच एक बेहद बड़ा अंतर है, जिसे दूर किए बिना प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बनाए रखना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के इन स्पष्ट और कठोर निर्देशों ने इस मुद्दे को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि न्यायपालिका की सीधी चेतावनी है कि यदि बीएलओ की सुरक्षा, मानसिक दबाव और कार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो यह प्रक्रिया देश के चुनावी ढांचे को कमजोर कर सकती है। आने वाले दिनों में राज्य सरकारें और निर्वाचन आयोग किस दिशा में कदम उठाते हैं, यह देखने लायक होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने संकेत दे दिया है—मतदाता सूची बनाने वाला हर बीएलओ सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और उसकी सुरक्षा, सम्मान तथा सुविधा की अनदेखी अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग; पूरी रात चली तलाशी, यात्री सहमे

(जीएनएस)। मदीना से उड़ान भरकर हैदराबाद की ओर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट बुधवार देर रात उस समय दहशत में बदल गई, जब गंतव्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर अहमदाबाद में उसकी अचानक आपात लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को शुरुआत में समझ नहीं आया कि आखिर विमान को बीच रास्ते में क्यों उतारा जा रहा है, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि फ्लाइट को एक ई-मेल के जरिए बम रखने की धमकी मिली है, पूरे विमान में सन्नाटा पसर गया।

गुजरात के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई। रनवे से लेकर टर्मिनल तक हर हिस्से में सीआईएसएफ की तैनाती बढ़ा दी गई। प्लेन को एक सुरक्षित बे में ले जाया गया और यात्रियों को क्रमवार उतारकर एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। कई यात्री घबराए हुए थे, कुछ लोग बेचैनी में बार-बार फोन मिलाकर अपने परिजनों को हालात बता रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ और पुलिस ने स्थिति को शांत रखने की कोशिश जारी रखी।

सूत्रों के मुताबिक, एयरलाइंस को एक ई-मेल मिला था जिसमें दावा किया गया था कि विमान में बम लगाया गया है। जैसे ही यह मेल आया, कंट्रोल रूम से तुरंत पायलट को सूचना भेजी गई और लगभग उसी क्षण विमान को डायवर्ट करने का निर्णय ले लिया गया। कैप्टन ने पूरी सावधानी के साथ विमान को अहमदाबाद में सुरक्षित उतार लिया।

लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर पुलिस, सीआईएसएफ, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोज़ल स्क्वाड की टीमें एक साथ जुट गईं। फ्लाइट के अंदर लगी सीटों से लेकर ओवरहेड बिन्स, यात्रियों के बैग, कार्गो सेक्शन और हर छोटे-छोटे कोने की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। एसओपी के तहत विमान को पूरी तरह खाली कराकर सील कर दिया गया और यात्रियों के बैग अलग-अलग लाइनों में रखकर स्निफर डॉग्स की मदद से चेक किए जा रहे हैं।

अहमदाबाद ज़ोन-4 के डीसीपी अतुल बंसल ने बताया कि जैसी ही जानकारी मिली, पुलिस की टीमें तुरंत एयरपोर्ट पर भेज दी गईं। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह धमकी महज़ अफवाह थी या किसी योजना का हिस्सा—इसकी जांच कई स्तरों पर की जा रही है।

रात भर एयरपोर्ट पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। यात्रियों में से कई लोग थकान में कुर्सियों पर बैठे रहे, जबकि कुछ लोग इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि विमान सुरक्षित उतर गया। अधिकारियों का कहना है कि जब तक तलाशी की सभी औपचारिकताएँ पूरी नहीं हो जातीं, किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

इमरजेंसी लैंडिंग की इस पूरी घटना ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया है कि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा कितनी संवेदनशील है और एक ई-मेल जैसी चीज़ भी सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित और सतर्क कार्रवाई की वजह से बड़े हादसे की आशंका टल गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

बीजापुर के जंगलों में दिनभर गूंजती रहीं गोलियाँ, मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर; तीन जवानों ने दी शहादत, इलाके में तनाव

(जीएनएस)। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर फैले वेस्ट बस्तर डिवीजन के घने जंगलों में बुधवार की सुबह किसी साधारण दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वही जंगल बंदूकों की गड़गड़ाहट, विस्फोटों की आवाज़ और धुएँ की गंध से भर गया। गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों का एक बड़ा दस्ता सर्च ऑपरेशन पर निकला था—डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम, जिन्हें इन पहाड़ी इलाकों की हर पगडंडी, हर मोड़ और हर जोखिम की पहचान अच्छी तरह है। फिर भी, उस दिन जंगल ने एक और चुनौती उनके सामने खड़ी कर दी। सुबह करीब नौ बजे, जब दल झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक आसपास की चट्टानों और पेड़ों के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। माओवादी दस्ते ने ऊँचाई वाले स्थानों से गोलियों की बौछार कर दी थी। पहले कुछ मिनटों में स्थिति इतनी तेजी से बदली कि सुरक्षा बलों को बिना पोजिशन गंवाए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। जंगलों में फैल चुके बारूद के धुएँ के बीच कई जगहों पर घंटों तक गोलीबारी चलती रही और धीरे-धीरे यह मुठभेड़ एक लंबे संघर्ष में बदल गई।

दोपहर तक कई घायल माओवादी गिरते दिखे। सुरक्षा बलों ने सावधानी से मोर्चा बदला और धीरे-धीरे इलाके को चारों तरफ से घेरा। शाम होने तक यह साफ हो चुका था कि माओवादी भारी नुकसान झेल चुके हैं। शुरुआत में 12 शव मिलने की पुष्टि हुई थी, लेकिन गुरुवार सुबह तलाशी अभियान बढ़ाया गया तो चार और शव झाड़ियों के बीच मिले। इस तरह कुल 16 माओवादी मारे जाने की पुष्टि हुई। बरामद हथियारों में एसएलआर, इंसास, 303 राइफल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद शामिल था, जो यह बताता है कि माओवादी दस्ते की तैयारी मजबूत थी।

लेकिन इस संघर्ष में सबसे बड़ा आघात सुरक्षा बलों ने झेला। डीआरजी के तीन जवान—प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोड़ी—ने गोलियों की बारिश के बीच अदम्य साहस दिखाया, लेकिन अंततः देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके शहीद होने की सूचना कैंप तक पहुँची तो पूरे दस्ते में गहरी चुप्पी फैल गई। दो और जवान घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई।

मुठभेड़ की जगह पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियाँ भेज दी गई हैं। हर दिशा से जंगल को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि माओवादी दस्ता बड़ा था और कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागे हो सकते हैं, इसलिए क्षेत्र की घेराबंदी मजबूत की गई है। पुलिस डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की रणनीति का अहम हिस्सा थी। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों की लगातार दबाव वाली कार्रवाइयों से माओवादी गतिविधियाँ कमज़ोर पड़ी हैं, लेकिन जंगलों के भीतर अभी भी उनका जटिल ढांचा मौजूद है, जिसे खत्म करने के लिए ऐसे ऑपरेशनों की आवश्यकता बनी हुई है।

बीजापुर का यह मुठभेड़ क्षेत्र अब भी तनाव में है। धूल, बारूद और झाड़ियों से भरे उन रास्तों पर आज भी जवानों के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। जंगल के बीच जहाँ कल गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, वहीं आज शहीद जवानों की वीरता और माओवादियों की पराजय की कहानियाँ फुसफुसा रही हैं। इस लड़ाई में 16 माओवादी ढेर हुए—लेकिन सुरक्षा बलों के तीन वीर जवानों की शहादत यह याद दिलाती है कि नक्सलवाद के खिलाफ यह संघर्ष कितना कठिन और महँगा है।

नेपाल यात्रा के लिए बड़ी राहत: अब ले जा सकेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, आरबीआई ने बदले नियम; पर्यटकों–श्रमिकों को बड़ा फायदा

(जीएनएस)। भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए गुरुवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन के पुराने प्रावधानों में बड़ा संशोधन करते हुए 200 और 500 के भारतीय नोट नेपाल ले जाने की अनुमति दे दी। लंबे समय से चली आ रही रोक और जटिल नियमों के कारण भारतीय यात्रियों और नेपाल में काम करने वाले श्रमिकों को भारी दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब नई व्यवस्था से दोनों देशों के बीच आवागमन अधिक सहज और सुविधाजनक हो जाएगा।

आरबीआई ने 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा निर्यात एवं आयात) संशोधन विनियमावली 2025' जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत से नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले लोग अब अधिकतम 25 हजार भारतीय रुपये लेकर जा सकेंगे। पहले 200 और 500 रुपये के नोट नेपाल ले जाने पर सख्त पाबंदी थी, जिसके कारण यात्रियों को या तो 100 रुपये के नोटों का भारी बोझ उठाना पड़ता था या पहुँचकर महँगे विनिमय दरों पर स्थानीय मुद्रा लेनी पड़ती थी।

नए नियमों के अनुसार अब 100 रुपये तक के नोटों पर तो पहले जैसी कोई रोक नहीं रहेगी ही, साथ ही 200 और 500 के बड़े नोट भी निर्धारित सीमा के भीतर लेकर जाने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, नेपाल और भूटान से भारत आने वाले यात्री भी 25 हजार रुपये तक के उच्च मूल्यवर्ग के भारतीय नोट साथ ला सकेंगे। इस संशोधन ने सीमा पार आवागमन करने वाले लोगों की वित्तीय परेशानी काफी हद तक कम कर दी है। हजारों नेपाली नागरिक जो भारत में काम करते हैं और हर महीने सीमा पार आना–जाना करते हैं, अब बिना किसी जोखिम और परेशानी के भारतीय मुद्रा साथ लेकर लौट सकेंगे। इसी तरह भारत से नेपाल घूमने वाले पर्यटक और व्यावसायिक उद्देश्य से यात्रा करने वाले लोग भी बड़ी मात्रा में छोटे नोटों की व्यवस्था करने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे।

हालाँकि यह छूट पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दी गई है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि संशोधित प्रावधान केवल नेपाल और भूटान के लिए लागू होंगे, वहीं दोनों देशों की स्थानीय मुद्राएँ भी भारत के बाहर इन्हीं दो देशों में ले जाई और लाई जा सकेंगी।

नेपाल में बड़े भारतीय नोटों के उपयोग पर पहले लगी थी रोक, जिसने व्यापारियों, पर्यटकों और भारतीय श्रमिकों को भारी परेशानी में डाल दिया था। लेकिन अब, नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा समान व्यवस्था लागू किए जाने के बाद नया नियम कारगर हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और श्रमिकों की आवाजाही को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

आरबीआई के इस फैसले ने हजारों यात्रियों को राहत की सांस दी है और भारत–नेपाल संबंधों में आर्थिक लेनदेन की सहजता को एक नई दिशा प्रदान की है।

असम में तीन जिहादी संगठन प्रतिबंधित, सीआईडी इनपुट पर तत्काळ कार्रवाई; राज्य सुरक्षा पर मंडराते खतरे के बीच कड़ा कदम

(जीएनएस)। असम सरकार ने राज्य की सुरक्षा पर मंडराते खतरों के मद्देनज़र गुरुवार को एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। राज्य के गृह विभाग ने अपराध अन्वेषण शाखा (सीआईडी) से मिले गोपनीय और अत्यंत संवेदनशील इनपुट के आधार पर तीन सक्रिय जिहादी संगठनों—जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बंगला टीम और अल-कायदा से जुड़े अंसार-उल-इस्लाम—को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित घोषित कर दिया। इस फैसले ने पूरे राज्य के सुरक्षा तंत्र में एक नई सतर्कता की लहर पैदा कर दी है। गृह विभाग ने विस्तृत अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पिछले कुछ महीनों से राज्य में इन संगठनों की गुप्त गतिविधियों से जुड़े कई प्रमाण सीआईडी को मिले थे। इन प्रमाणों में न केवल संचार तंत्र और फंडिंग नेटवर्क की सूचनाएँ शामिल थीं, बल्कि राज्य में संभावित भर्ती प्रयासों से जुड़े कुछ अहम सुराग भी मिले थे। अधिकारियों का कहना है कि इन संगठनों की गतिविधियाँ असम की आंतरिक सुरक्षा, जन-शांति और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थीं। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल प्रतिबंध लागू किया गया।

जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और अंसारुल्लाह बंगला टीम पूरे पूर्वोत्तर में पहले भी कई बार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रह चुके हैं। वहीं अंसार-उल-इस्लाम, जो अल-कायदा समर्थित नेटवर्क से जुड़ा हुआ माना जाता है, अपनी ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए बदनाम है। सीआईडी ने इन तीनों संगठनों के आपसी कनेक्शन और सीमापार संचालित नेटवर्क को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद प्रतिबंध का यह निर्णय लिया गया।

गृह विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति, समूह, संगठन या डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया प्रचार-प्रसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा। यह धाराएँ न सिर्फ कठोर दंड का प्रावधान करती हैं, बल्कि संपत्ति की जब्ती तक की कार्रवाई को भी संभव बनाती हैं।

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि, पोस्ट, संदेश या बैठक की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें। साथ ही यह भी कहा गया है कि युवा वर्ग को कट्टरपंथी संगठनों की ऑनलाइन ब्रेनवॉश रणनीतियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई भर्ती प्रयास सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट प्लेटफार्मों के माध्यम से किए जाते रहे हैं।

असम सरकार की यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब राज्य पिछले कुछ वर्षों में चरमपंथी नेटवर्कों द्वारा संभावित विस्तार की चुनौती झेल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह प्रतिबंध इन संगठनों की गतिविधियों को कमजोर करेगा और राज्य में कट्टरपंथ के फैलाव पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निर्णय के साथ असम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य की सुरक्षा और शांति से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

सरकारी यू टर्न के बावजूद उठे सवाल

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि आगामी वर्ष मार्च से हर नये स्मार्टफोन में 'संचार साथी' ऐप पहले इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर पुराने स्मार्ट फोनों में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा भेजा जाएगा। जिसको लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष का कहना था कि इससे निजता का उल्लंघन होगा और व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल, सरकार का कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप से नई तरह की असुरक्षा पैदा हो सकती है। बताया जाता है कि सरकार ने स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप इस तरह इंस्टाल करने को कहा था ताकि उसे डिलीट या अक्षम न किया जा सके। केंद्र की दलील थी कि यह ऐप उपभोक्ता को धोखाधड़ी वाले फोन और संदेशों की रिपोर्ट लिखवाने में मदद करता। साथ ही चोरी किए गए मोबाइल की बरामदगी आसान हो पाती। लेकिन निजी डेटा सुरक्षा व इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके चलते इसका विरोध हुआ। वैसे सर्च इंजन में पहले से मौजूद इस ऐप को देश के लाखों लोग पहले ही स्वेच्छा से डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन इसको अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश के बाद विरोध के स्वर उभरने लगे। जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिये व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करके उसके जीवन में ताक-झांक की जा सकती है। हालांकि, विरोध के सुर मुखर होने के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया कि यह निर्णय वैकल्पिक है और कोई व्यक्ति इस ऐप को इच्छानुसार डिलीट कर सकता है। निस्संदेह, निजता हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे में किसी ऐप की अनिवार्यता से व्यक्ति की गोपनीयता में खलल पड़ने की आशंका जतायी जाने लगी। पिछले दिनों सरकार ने व्हाट्स ऐप व टेलीग्राम आदि कम्युनिकेशन ऐप्स संचालक कंपनियों से कहा था कि वे अपनी सेवा को मोबाइल के सिम कार्ड से जोड़कर रखें। ताकि सिम के बिना इन ऐप का दुरुपयोग न हो सके। जिसको लेकर टेलि-कम्युनिकेशन कंपनियों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया था। निस्संदेह, निजता का अधिकार देश में मौलिक अधिकार के रूप में मौजूद है। शीर्ष अदालत ने भी अपने एक निर्णय के जरिये स्पष्ट किया था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 में 'राइट टू प्राइवेसी' में भी निहित है। जिसके अंतर्गत मोबाइल, इंटरनेट व डिजिटल जानकारियां भी शामिल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से इतर व्यक्ति को अपनी डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा का हक है। यही वजह है कि विगत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोबाइल व निजी कंपनियां उपभोक्ता से आधार कार्ड नहीं मांग सकती। इस फैसले को तब निजता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। यही वजह है कि 'संचार साथी' की अनिवार्यता के बाद निजता व व्यक्ति के डेटा में सरकारी दखल को लेकर सवाल उठने लगे। निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं कुछ अन्य ऐप हमारे डेटा में तो सेंध नहीं लगा रहे हैं? सरकार को इससे उपभोक्ता की सुरक्षा करनी होगी। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बजाय आम लोगों को नई तकनीक और इसके इस्तेमाल के लिये सतर्क करने को देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिये आम जनता को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को गति दी जा सके।

अमेरिकी दबाव के बावजूद परवान चढ़ती दोस्ती

"भारत और रूस के बीच 'स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' है, जिसके तहत एसयू-57 फ़ाइटर जेट और मिसाइल डिफ़ेंस शील्ड एस-500 के एडवांस्ड वर्शन की खरीद पर बातचीत होने की उम्मीद है। यह समझौता अमेरिका के साथ किसी भी ट्रेड डील को मुश्किल बना सकता है।"

इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 दिसंबर को दो दिन के वास्ते स्टेट विज़िट पर आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। फरवरी, 2022 में यूक्रेन में युद्ध आरंभ होने के बाद से पुतिन का यह पहला आधिकारिक आगमन होगा। पुतिन, पिछली बार यूक्रेन युद्ध से कुछ माह पहले, दिसंबर 2021 में भारत आए थे। रूसी राष्ट्रपति का रेड-कार्पेट वेलकम साउथ ब्लॉक में किया जाएगा, जहां 23वीं सालाना इंडिया-रूस शिखर बैठक होगी।

भारत और रूस के बीच 'स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' है, जिसके तहत एसयू-57 फ़ाइटर जेट और मिसाइल डिफ़ेंस शील्ड एस-500 के एडवांस्ड वर्शन की खरीद पर बातचीत होने की उम्मीद है। यह समझौता अमेरिका के साथ किसी भी ट्रेड डील को मुश्किल बना सकता है, जिसने मॉस्को से भारत के हथियारों की खरीद को पीछे धकेल दिया है।

ठीक से देखा जाये, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति संतुलन सिद्धांत को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाये रखना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप का हठयोग इस मार्ग में बाधा पैदा कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में खत्म होने वाले चार सालों में रूसी हथियारों की खरीद में काफी गिरावट के बावजूद मॉस्को भारत का सबसे बड़ा मिलिटरी हार्डवेयर सप्लायर बना हुआ है।

भारत के पास 200 से ज़्यादा रूसी फाइटर जेट और एस-400 डिफेंस शील्ड की कई बैटरी हैं, जिनका इस्तेमाल मई में पाकिस्तान के साथ चार दिन की लड़ाई के दौरान किया गया था। रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं, कि भारत की सेना के पास फाइटर जेट की कमी है, और सरकार से इस कमी को पूरा करने के लिए रूस निर्मित एडवांस्ड फाइटर जेट खरीदने का आग्रह किया है। सूत्र यह भी बताते हैं, कि एसयू -57 जेट में लगी लंबी दूरी की मिसाइलें दक्षिण एशियाई देश को ज़्यादा विजुअल रेंज कैपेबिलिटी देंगी। हालांकि, रूस-भारत के बीच हुए समझौते को स्टेट ड्यूमा में मंज़ूरी मिलनी बाकी है। दो दिन की शिखर बैठक में, दोनों पक्ष डिफेंस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर

एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, स्पेस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर चर्चा करेंगे।

चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर एनआर भानुमूर्ति के मुताबिक, भारत के लिए 93 मिलियन डॉलर के हथियारों के सौदे को वॉशिंगटन की मंज़ूरी, महीनों के ट्रेड टेंशन के बाद दोनों पक्षों के बीच रिश्तों में सुधार का संकेत है, और यह अगले साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नई दिल्ली दौरे की संभावित शुरुआत भी है। यूक्रेन शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई पावर्ड अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को में है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूत नाम स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर इस हफ़्ते डील की कोशिश के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। यूक्रेन में शांति से दिल्ली का फ़ायदा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर शुरू में 25 प्रतिशत इंपोर्ट टैरिफ लगाया था, फिर इसे बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया। यह टैरिफ दिल्ली द्वारा रूसी तेल खरीदने पर पेनल्टी थी। उन्होंने कहा कि यह तेल खरीद यूक्रेन से युद्ध के वास्ते मॉस्को को आर्थिक मज़बूती दे रही थी। चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर एनआर भानुमूर्ति मानते हैं कि कई भारतीय तेल कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, इसलिए आने वाले हफ्तों में भारत पर अमेरिकी टैरिफ कम होने की संभावना है।

उनके बरक्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर में इंस्टिट्यूट ऑफ़ साउथ एशियन स्टडीज़ के सीनियर रिसर्च फेलो अमितेंदु पालित का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, इसका असर सिर्फ़ जुलाई-सितंबर वाली तिमाही में महसूस हुआ। अमितेंदु ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड संबंध हाल ही में बेहतर हुए हैं। पिछले महीने अमेरिका से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खरीदने के लिए सरकारी भारतीय तेल कंपनियों द्वारा साइन किए गए एक साल के अनुबंध पर ग़ौर करना चाहिए।

ज़रूरी नहीं कि जो तर्क अमितेंदु दे रहे हों, उसके आधार पर मान लें कि सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा है। आईएमएफ के ज़रिये भी अमेरिकी प्रशासन मोदी सरकार पर दबाव बनाये हुए है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने पिछले हफ्ते भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया था। यह बताया गया कि आईएमएफ को दी गई जानकारी में 'कुछ कमियां थीं जो कुछ हद तक सर्विलांस में रुकावट डालती हैं'। तो क्या आईएमएफ की शंकाओं को दूर करने के लिए भारत के इकोनॉमिक डेटा में बदलाव किए जाने की संभावना है?

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 'क्रेमलिन लॉन्ड्रोमैट' कहा और भारतीय इम्पोर्ट पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच बीच-बचाव करने की उनकी लगातार दावेदारी ने भी भारतीय रणनीति के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। नई दिल्ली द्वारा बार-बार मना करने के बावजूद ट्रम्प यह कहने से बाज़ नहीं आते, कि उनकी वजह से भारत-पाक के बीच युद्धविराम हुआ।

मोदी प्रशासन ने ब्रिक्स और एससीओ फ्रेमवर्क में साथ काम करके बहुत अनुभव हासिल किया है। इन बैठकों में 'एस-500 समेत नेक्स्ट-जेनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम' की सप्लाई और लोकल प्रोडक्शन के लिए मिलिटरी ठेके मिलने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने रूसी मिसाइल कवच 'एस-400' की बहुत तारीफ़ की थी। चीन और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर भारत के मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस में एस-400 को इंटीग्रेट करना एक अहम सुरक्षा तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। एस-400 सपोर्ट सिस्टम का लगभग आधा हिस्सा लोकलाइज़ किया जा सकता है, अर्थात इसके साज़ो-सामान से सम्बंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिल जाना पुतिन की यात्रा को उल्लेखनीय बना देगा। यह भी अहम है कि एसयू-57 फाइटर जेट उड़ाने के लिए इंडियन एयरफ़ोर्स के पायलट तैयार हैं।

एक और आवश्यक विषय रूसी तेल आयात है। यूक्रेन में मिलिटरी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से भारत के इम्पोर्ट में 600 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे भारत रूसी तेल का 38 प्रतिशत खरीदार बन गया था। लेकिन, दो दिनों से भारतीय मीडिया में यह खबर भी चलाई जा रही है कि प्रतिबंधों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों ने फिलहाल आयात रोक दिया है।

प्रेरणा

एक उजाले की ओर बढ़ता मनः स्वामी रामतीर्थ की अद्भुत ज्ञान-यात्रा

पंजाब के गुजरांवाला जिले का शांत और मिट्टी की महक से भरा मुरारीवाला ग्राम, देखने में भले साधारण लगता हो, लेकिन इसी धरती पर एक असाधारण बालक ने जन्म लिया—रामतीर्थ—जिसकी प्रतिभा, जिज्ञासा और आत्मिक आभा ने जन्म लेते ही अपने भविष्य की दिशा तय कर दी थी। बचपन से ही उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी, और दिमाग में सवालों का असीम ब्रह्मांड। जहाँ दूसरे बच्चे खेलों में रमते, वहीं रामतीर्थ की दुनिया किताबों और विचारों में बसती थी। वह केवल पढ़ते नहीं थे, बल्कि ज्ञान को जीते थे।

समय बीतता गया और अध्ययन के प्रति उनकी रुचि इतनी गहरी होती गई कि जल्द ही वे अपने शिक्षकों के प्रिय और सहपाठियों के प्रेरणास्रोत बन गए। 1891 में जब उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की बी.ए. परीक्षा पूरे प्रांत में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण की, तो हर कोई उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो गया। दस रुपये की मासिक छात्रवृत्ति उन्हें सम्मान, प्रेरणा और उपलब्धि—तीनों का मिश्रित उपहार थी। यह वही समय था जब ज्ञान उनके भीतर साधना का रूप लेने लगा था। उन्होंने एम.ए. की परीक्षा भी सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की, मानो ब्रह्मांड ने उनके कदमों के नीचे रास्ते खुद बिछा दिए हों। उनकी प्रतिभा के चलते उन्हें उसी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर की प्रतिष्ठित कुर्सी मिली।

लेकिन मनुष्य मन का स्वभाव विचित्र होता है। बाहर की उपलब्धियाँ कभी-कभी भीतर की पुकार को और तेज कर देती हैं। गणित पढ़ाते हुए, सूत्रों को समझाते हुए, विद्यार्थियों को नई दृष्टि देते हुए भी रामतीर्थ के भीतर धीरे-धीरे एक अलग ही दिशा जागने लगी—एक ऐसी दिशा जो इस भौतिक संसार से बहुत आगे थी। गणित की जटिलताओं को सुलझाते हुए भी उनके भीतर यह प्रश्न उठने लगा कि जीवन का अंतिम 'समीकरण' क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ है? और सत्य का वास्तविक स्रोत क्या है?

यह प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। यही प्रश्न उन्हें वैराग्य की ओर ले गया। और 1901 में वे बिना किसी घोषणा, बिना किसी विदाई, चुपचाप लाहौर छोड़कर उत्तराखंड की शांत, दिव्य और साधना से भरी भूमि की ओर निकल पड़े। टिहरी गढ़वाल के कोटी ग्राम में एक शाल्माली वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की—श्रद्धा, ध्यान और साधना से भरी हुई शुरुआत। इसी वृक्ष की छाया में उन्होंने पहला कदम उठाया—और प्रोफेसर रामतीर्थ धीरे-धीरे स्वामी रामतीर्थ बनते चले गए।

उनकी साधना केवल भीतर की यात्रा नहीं थी; यह दुनिया के भ्रम से निकलकर सत्य तक पहुँचने का मार्ग था। पहाड़ों की शांति, गंगा की ध्वनि और जंगल की निस्तब्धता में बैठकर वे अपने भीतर उस ब्रह्म-ज्योति को खोजने लगे जिसके बारे में शास्त्र कहते थे, लेकिन जिसे अनुभव करना एक अलग ही दिव्यता थी। इसी साधना के दिनों में टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा, कीर्तिशाह, जो स्वयं को कट्टर नास्तिक मानते थे, स्वामी रामतीर्थ के पास तर्क-वितर्क करने आए।

राजा की मनोदशा में चुनौती थी, तर्कों का तेज था, संशय था और अहंकार भी। लेकिन सामने बैठे थे ऐसे व्यक्ति जिनकी वाणी में अग्नि नहीं, शांति थी; जिनके शब्दों में तर्क था, लेकिन तर्क के भीतर करुणा थी; जिनकी दृष्टि में स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों थे। स्वामी रामतीर्थ ने किसी वाद-विवाद की मुद्रा नहीं अपनाई। उन्होंने बस सहजता से, विनम्रता से, गहराई से जीवन और सत्य के बारे में बातें कीं। उनके ज्ञान की व्यापकता और आत्मा की स्वच्छता के सामने राजा की सारी शंकाएँ धीरे-धीरे मिटती चली गईं। कुछ ही देर बाद राजा का अहंकार टूट चुका था। उनकी आँखों में वह विनम्रता लौट आई थी जो केवल सच्चे ज्ञान के सामने आती है। वे स्वामी रामतीर्थ के चरणों में गिर पड़े और एक नास्तिक मन आस्तिक आस्था में बदल गया। इस घटना ने स्वामी रामतीर्थ को केवल एक साधक ही नहीं, बल्कि सत्य के दूत के रूप में स्थापित कर दिया।

राजा ने सम्मानपूर्वक उन्हें जापान में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा। वहाँ स्वामी रामतीर्थ ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा, उसके ज्ञान, उसके दर्शन और उसकी गहन संस्कृति को दुनिया के सामने इस तरह प्रस्तुत किया कि पूरा सभागार मंत्रमुग्ध हो गया। वे गणितज्ञ थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक भाषा गणित के सूत्रों से भी अधिक सटीक, संतुलित और प्रभावी थी। उनकी वाणी में करुणा थी, विचारों में शक्ति थी और आत्मा में एक दिव्यता थी जो उनके सामने बैठे हर व्यक्ति के मन को छू जाती थी। वे केवल एक प्रवचनकर्ता नहीं थे; वे एक आंदोलन थे, एक प्रकाश थे, मनुष्यता का वह स्वर थे जो भीतर सोई संभावनाओं को जगाने का सामर्थ्य रखता है।

समय अपनी गति से चलता रहा, और आखिरकार वह क्षण भी आया जब स्वामी रामतीर्थ की साधना अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। दीपावली का दिन था—प्रकाश का पर्व। उसी पावन दिन उन्होंने गंगा में जलसमाधि लेकर अपने जीवन की देह-यात्रा समाप्त की। यह मृत्यु नहीं थी, यह मुक्ति थी। यह अंत नहीं था, यह अनंत से मिलन था।

आज भी जब उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो लगता है कि उनका जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है—कि ज्ञान का सबसे ऊँचा शिखर वही है जहाँ मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगता है। उनकी यात्रा बताती है कि अध्यापन की उत्कृष्टता से लेकर आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा तक का मार्ग एक ही व्यक्ति के भीतर सम्भव है, यदि उसकी लगन सच्ची हो और उसकी दृष्टि निर्मल।

उनकी कहानी आज भी उन सभी के लिए एक दीपक है जो जीवन के अंधकार में प्रकाश तलाश रहे हैं, और उन सबके लिए एक पथ है जो ज्ञान की वास्तविक जीत को समझना चाहते हैं।

नए भारत को सुरक्षा एवं संवेदना वाली नई पुलिस चाहिए

भारतीय लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था कानून-व्यवस्था की आधारभूत धुरी है, परंतु आम नागरिक के मानस में पुलिस की छवि अभी भी कठोरता, डर और दमन से जुड़ी हुई है। इसे केवल अधिकार जताने वाली शक्ति समझा गया है, संवेदनशीलता, जवाबदेही और मित्र भाव से नहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में इसी जटिलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस की छवि तभी बदलेगी जब व्यवस्था अधिक प्रोफेशनल, अधिक उत्तरदायी और अधिक मानवीय बने। विकसित भारत की दृष्टि में पुलिस का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि समाज में भरोसे को पुनर्जीवित करने का कार्य भी है। पुलिस के पास अपराध नियंत्रण, आतंकवाद-निरोध, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, चुनाव ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा जैसी असंख्य जिम्मेदारियां हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं, कार्य-भार भारी और राजनीतिक दबाव व्यापक हैं। कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट या कठोर व्यवहार ने संपूर्ण पुलिस व्यवस्था की छवि पर चोट पहुंचाई है, इसलिए जनता पुलिस के निकट आने पर भी भय का अनुभव करती है। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति बदलने की स्पष्ट आवश्यकता जताई और युवाओं में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण पर बल दिया ताकि आने वाली पीढ़ी पुलिस को मित्र और संरक्षणकर्ता के रूप में पहचाने।भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक स्तंभों में पुलिस की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। वह केवल अपराधियों से मुकाबला करने वाली शक्ति नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था, नैतिकता और जनविश्वास की संरक्षक है। परंतु विडम्बना यह है कि आम जनता के मानस में पुलिस की छवि आज भी कठोरता, डर, भ्रष्टाचार और दमन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। समाज पुलिस को "डंडे" और "खाकी" के प्रतीक रूप में पहचानता है, संवेदनशीलता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से नहीं। यही कारण है कि पुलिस सुधार दशकों से विमर्श का विषय तो रहा, लेकिन कभी जनांदोलन नहीं बन सका, न चुनावी मुद्दा बना और न ही गंभीर राजनीतिक प्राथमिकता। इसलिये मोदी ने शहरी पुलिसिंग को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को फिर से सक्रिय करने, विश्वविद्यालयों को फोरेंसिक अध्ययन के लिए प्रेरित करने और नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा नागरिक सुरक्षा संहिता पर व्यापक जनजागरूकता चलाने की जरूरत रेखांकित की। उनका यह दृष्टिकोण पुलिस को प्रतिक्रियाशील संस्था से आगे बढ़ाकर बुद्धिमान, वैज्ञानिक, पूर्वानुमान आधारित और विश्वसनीय संस्था बनाने की दिशा है। प्रधानमंत्री की दृष्टि का महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली मशीन नहीं बल्कि समाज का सहभागी तंत्र है। यदि पुलिस व्यवहार में संवेदनशीलता, संवाद, पारदर्शिता और विनम्रता विकसित करे तो जनविश्वास स्वतः बढ़ेगा। नए कानूनों के बारे में जन-जागरूकता अभियान इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब जनता उन्हें समझती और स्वीकार करती है। अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए पुलिस का प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता, इंटेलिजेंस नेटवर्क और फोरेंसिक क्षमता मजबूत होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने नेटग्रिड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकीकृत डेटाबेस के प्रभावी उपयोग पर जोर देकर पुलिसिंग को डेटा आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने की दिशा दिखाई है। उन्होंने प्रतिबंधित संगठनों की सतत निगरानी, नशीली दवाओं के विरुद्ध बहुस्तरीय रणनीति, कट्टरपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में विकास आधारित समाधान, तटीय सुरक्षा के नवाचार, तथा प्राकृतिक आपदाओं में सक्रिय पुलिस नेतृत्व की आवश्यकता भी व्यक्त की। यह सब उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें पुलिस केवल अपराध से लड़ने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि विकास की रणनीतिक सहभागी शक्ति है। परंतु पुलिस सुधार केवल निर्देशों से संभव नहीं; इसके लिए संतुलित एवं अत्याधुनिक ढांचे की जरूरत है जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन, मनोबल, आचार-नीति, राजनीतिक निर्भरताओं से मुक्ति और सामाजिक सम्मान शामिल हों। आलोचना जितनी महत्वपूर्ण है, पुलिस के संघर्षों को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इसी दोतरफा समझ से सुधार का रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि पुलिस नेतृत्व खुद को नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करे, लक्ष्य स्पष्ट करे और वह व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिक पुलिस को भय से नहीं बल्कि विश्वास से देखें। विकसित भारत की यात्रा में सुरक्षा, न्यायबोध और अनुशासन की संरचना को सशक्त बनाने के लिए पुलिस का आधुनिक, मानवीय और विश्वसनीय स्वरूप अनिवार्य है। यह सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और चरित्र का परिवर्तन है। तभी खाकी का सम्मान लौटेगा, जनता का विश्वास मजबूत होगा और पुलिस व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में पहचानी जाएगी। प्रधानमंत्री के ताजा विचारों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की छवि सुधारने का अर्थ केवल कठोरता घटाना नहीं, बल्कि उसे प्रोफेशनल, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस व्यवस्था के लिए भय का नहीं, विश्वास और सुरक्षा का केंद्र बने। शहरी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, पर्यटक पुलिस को पुनर्जीवित करने और नए आपराधिक कानूनों पर जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पुलिस "डंडे की ताकत" से आगे बढ़कर "मदद की शक्ति" बनेगी। यदि नागरिक को यह अनुभव होने लगे कि पुलिस मदद के लिए तत्पर है, उसके अधिकारों का सम्मान करती है और कानून का निष्पक्ष पालन करती है, तो खाकी वर्दी का अर्थ केवल अनुशासन नहीं बल्कि विश्वास, अभय और सहारा प्रतीत होगा। यही वह परिवर्तन है जो विकसित भारत की सोच में निहित है। अंग्रेजी शासकों ने अपने शासन को थोपने, जनता को नियंत्रित करने और भय-आधारित प्रशासन चलाने हेतु पुलिस तंत्र की रचना की। 1860 के कानून के आधार पर स्थापित भारतीय पुलिस का मूल चरित्र दंडात्मक, शासक-केन्द्रित और कठोर शक्ति-प्रयोग वाला था। स्वतंत्रता के बाद भी इस व्यवस्था में सार्थक बदलाव न होना एक विडंबना है।

अभियान

आत्मज्ञान, योग साधना और प्रकृति के अद्वितीय गुरु की दिव्य स्मृति का पर्व

दत्तात्रेय जयंतीः त्रिदेव के दिव्य अवतार, प्रकृति के शाश्वत गुरु और आत्मज्ञान की अनंत साधना की अद्भुत कथा

दत्तात्रेय जयंती भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का वह पावन पर्व है जिस पर केवल देवत्व ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, साधना, प्रकृति और गुरु-परंपरा की असाधारण महिमा एक साथ प्रत्यक्ष होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह दिन हजारों वर्षों से साधकों, योगियों, तपस्वियों और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह तिथि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने, अपनी चेतना को समझने और जीवन के गहरे अर्थ को अनुभव करने का अवसर है। दत्तात्रेय जयंती का हर क्षण व्यक्ति को यह स्मरण कराता है कि दिव्यता कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके ही भीतर निवास करती है।

पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु और महेश—के संयुक्त अवतार हैं। यह कथानक उतना ही दिव्य है जितना अद्वितीय। ऋषि अत्रि और देवी अनसूया के घर में जन्मे दत्तात्रेय की उत्पत्ति स्वयं प्रकृति के नियमों की तरह शाश्वत और रहस्यमय है। एक कथा के अनुसार, त्रिदेव देवी अनसूया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लेने उनके आश्रम पहुँचे। अनसूया की महान तपस्या और पवित्रता से प्रसन्न होकर वे एक ही रूप में प्रकट हुए और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। इसीलिए दत्तात्रेय को "त्रिगुणात्मक पुरुष" कहा जाता है—जो सृष्टि, पालन और संहार जैसे तीनों ही दिव्य गुणों का समन्वित रूप हैं।

दत्तात्रेय का चरित्र भारतीय योग-परंपरा का ऐसा स्तंभ है जिस पर अध्यात्म, संयम, भक्ति, ज्ञान और त्याग जैसे सभी गुणों की नींव रखी गई है। उन्हें योगियों का गुरु और गुरु-परंपरा का आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि उनका जीवन किसी एक स्थान या एक नियम में बंधा नहीं था। वे भिक्षाटन में, योग-साधना में, वन्य प्रदेशों में, पर्वतों में, शांत नदी किनारों पर और प्रकृति की गहराई में विचरण करते हुए स्वयं को निरंतर साधते रहे। उनका मार्ग संसार से दूर जाने का नहीं, बल्कि संसार को भीतर समाहित कर, उसमें रहने वाली परम शांति को पहचानने का था। उनके जीवन का सबसे महान संदेश वह है जिसे "24 गुरु" कहा जाता है। दत्तात्रेय ने इस जगत के हर तत्व—पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, पर्वत, नदी, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, समुद्र, कमल, सर्प और यहां तक कि साधारण वृक्षों से भी जीवन के रहस्य सीखे। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड एक खुली आध्यात्मिक पाठशाला था। वे कहते थे कि सीखना तब शुरू होता है जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है और प्रकृति को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। उनके अनुसार, यदि मनुष्य खुला मन रखे तो हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति उसके जीवन का शिक्षक बन सकती है। दत्तात्रेय जयंती के दिन भक्त व्रत रखते हैं, मन को शांत करते हैं और "ॐ द्रम दत्तात्रेयाय नमः" मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र मन की अशांति को दूर कर शांति और स्थिरता प्रदान करने वाला माना जाता है। दत्तात्रेय चालीसा और दत्त स्तोत्र का पाठ भक्त को वैराग्य, ज्ञान और शक्ति से भरते हैं। अनेक लोग पूरे दिन ध्यान में लीन रहते हैं ताकि भीतर की आवाज़ सुनी जा सके जिसे सामान्य दिनों की भागदौड़ में हम अक्सर अनसुना कर देते हैं।

भारत के कई तीर्थों पर इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। गुजरात का गिरनार पर्वत, महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश का पिथापुरम और कर्नाटक का नारायणपुर—ये सभी स्थान उस दिव्य ऊर्जा से भर उठते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। हजारों साधक और भक्त इन स्थानों पर एकत्र होते हैं, मानो समस्त वातावरण ही दिव्यता की तरंगों से भर गया हो। हर तरफ दीपों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि, भजन-कीर्तन की गूंज और साधकों की ध्यानमग्न मुद्रा इस पर्व को आध्यात्मिक आस्था का चरम अनुभव बना देती है। दत्तात्रेय जयंती केवल पूजन का दिन नहीं, बल्कि आत्मावलोकन का भी अवसर है। यह व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि भीतर की मौन शांति में छिपा है। दत्तात्रेय का मार्ग मनुष्य को यह सिखाता है कि इच्छाओं की भीड़ जितनी कम होगी, मन उतना ही हल्का होगा। संसार की आपाधापी में भटकता व्यक्ति इस दिन ठहरकर यह समझ सकता है कि सच्चा गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दिखाता है। यह गुरु बाहरी भी हो सकता है, और भीतर भी। दत्तात्रेय जयंती हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति का हर रंग, हर लय, हर परिवर्तन अपने भीतर कोई न कोई गहरा संदेश छिपाए हुए है। यदि हम उसे समझने का प्रयास करें, तो जीवन एक निरंतर सीखने की यात्रा बन जाता है। दत्तात्रेय का जीवन यह स्वीकार करता है कि मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, प्रकृति हमेशा उससे कई कदम आगे ही रहती है। इसलिए उसके साथ संवाद करना, उसे प्रणाम करना और उससे सीखना ही मनुष्य के लिए वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। यह पर्व व्यक्ति को यह संदेश देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है—अपनी चेतना, अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य और अपनी दिशा को पहचानना है। दत्तात्रेय जयंती मनुष्य को भीतर के प्रकाश की पहचान कराती है और उसे उस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जहाँ शांति, संतोष, ज्ञान और दिव्यता एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि यह पर्व सदियों से साधना, भक्ति, त्याग और आत्मज्ञान का प्रतीक बनकर आज भी उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है जितना प्राचीन काल में।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में 9000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का गौरवशाली समारोह आयोजित

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- आंगनबाड़ी बच्चे के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है
- राज्य में 53,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत, 170 और आंगनबाड़ी केंद्रों का ई-लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न
- राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नारी शक्ति से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए माता के पोषण एवं स्वास्थ्य के साथ ही बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 'विकसित भारत@2047' के लिए स्वस्थ पीढ़ी तैयार करने की अहम जिम्मेदारी निभानी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल सरकारी सेवा में नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को और भी सशक्त बनाने के मिशन में जुड़ीं हैं : डॉ. मनीषाबेन वकील, महिला एवं बाल विकास मंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में महिला एवं बाल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. मनीषाबेन वकील की प्रेरक उपस्थिति में राज्य की आंगनबाड़ियों में नवनियुक्त 9000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राज्यभर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के जोनवार कार्यक्रमों में मंत्रियों और पदाधिकारियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और सभी ने गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण देखा।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को बधाई देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी बच्चे के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। आंगनबाड़ी बहनों को देश के भविष्य इन नन्हें बच्चों के समृद्ध विकास की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है।

उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों का आह्वान किया कि वे उन्हें मिले 'सुपोषित और विकसित गुजरात से' 'विकसित भारत-समृद्ध भारत' बनाने के सेवा अवसर को सार्थक करने हेतु 'विकसित भारत@2047' के लिए स्वस्थ पीढ़ी तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारी शक्ति से राष्ट्र निर्माण का जो लक्ष्य दिया है, उसे साकार करने के लिए राज्य सरकार माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के साथ ही नन्हें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मानस का संस्कार सिंचन करके उन्हें भविष्य का नागरिक बनाने का दायित्व निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें माता यशोदा की तरह बच्चों का लालन-पालन और जीवन निर्माण करती हैं।

उन्होंने इस संदर्भ में इस बात का भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी बहनों को माता यशोदा का गौरव सम्मान दिया है और आंगनबाड़ी केंद्र को नंद घर की पहचान दी है। श्री पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने एक समय पुराने मकानों, पंचायत घरों और मंदिरों में चलने वाले बाल मंदिरों की स्थिति को बदलने का विजन दिया और गुजरात में संपूर्ण सुविधा युक्त आंगनबाड़ी-नंद घरों का निर्माण कराया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 53,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं।

मुख्यमंत्री ने इस समारोह में 170 और नए आंगनबाड़ी केंद्रों का ई-लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए आने वाले वर्षों में 10 हजार से अधिक नए नंद घर बनाने की राज्य सरकार की योजना की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण की निरंतर चिंता करते हुए राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए दूध संजीवनी योजना के तहत फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध के अलावा गर्भवती माताओं को प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने के लिए पोषण सुधा योजना, टेक होम राशन और मुख्यमंत्री मातृशक्ति जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी से लेकर प्राथमिक स्कूल तक के 41 लाख से अधिक बच्चों के लिए 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' भी शुरू की गई है।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. मनीषाबेन वकील ने राज्य की आंगनबाड़ियों में नियुक्ति पाने वाली सभी बहनों को बधाई दी और कहा कि आज से आप सभी सरकारी सेवा में नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को और अधिक सशक्त बनाने के मिशन में जुड़ी हैं। आप सभी कल के नागरिक यानी इन बच्चों की पहली शिक्षिका बनने जा रही हैं। आप जो संस्कार, शिक्षा और पोषण का बीज रोपेंगे, उसी से आने वाले कल का गुजरात खिलेगा।

उन्होंने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए ऊर्जा के केंद्र बताते हुए कहा कि गुजरात के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली है। नवनियुक्त बहनें स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनी हैं। ये बहनें राज्य में नारी सशक्तिकरण की नई गाथा लिखेंगी। उन्होंने कहा कि इन बहनों को दिए गए नियुक्ति पत्र केवल नियुक्ति पत्र ही नहीं, बल्कि बच्चों को सुपोषित और शिक्षित करने के दस्तावेज हैं।

डॉ. वकील ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र समाज निर्माण की सबसे बुनियादी इकाई है। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बच्चों को माता की गोद जैसी सुरक्षा, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा देती हैं। आंगनबाड़ी व्यवस्था सरकार की प्रत्येक योजना एवं प्रत्येक संदेश को सच्चे अर्थ में अंतिम छोर के लाभार्थी तक पहुंचाती है। राज्य सरकार की विभिन्न पोषण उन्मुख योजनाओं को बच्चों तक सही ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी कार्यकर्ताओं की है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सशक्त माता और स्वस्थ बालक के जरिए सुपोषित गुजरात बनाने के संकल्प में आप सभी शिल्पकार की भूमिका को भली-भांति निभाएंगे।

इसके साथ ही, राजकोट, सूरत और वडोदरा जोन की नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को भी जिला स्तर पर मंत्रियों और महानुभावों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषा वकील ने महात्मा मंदिर में 'पोषण नी सेवाओ, पा पा पगली – पूर्व प्राथमिक शिक्षण', डिजिटल पहल और पोषण संगम सहित विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर जानकारी हासिल की। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री राकेश शंकर ने अपने वक्तव्य में पूरे कार्यक्रम की विस्तृत भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गुजरात की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, खुशहाली और शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त आंगनबाड़ी बहनों को बधाई दी और देश के भविष्य के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में एकीकृत बाल विकास योजना आयुक्त श्री रणजीत कुमार सिंह ने आभार व्यक्त किया।

समारोह में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें मौजूद रहीं।

एमसीएक्स पर सोना वायदा 642 रुपये और चांदी वायदा 2704 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा में 18 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 34076.3 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 84233.1 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 25885.15 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 31070 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 118315. करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 34076.3 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 84233.1 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 31070 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1730.96 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 25885.15 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 130799 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 130799 रुपये और नीचे में 129454 रुपये पर पहुंचकर, 130462 रुपये के पिछले बंद के सामने 642 रुपये या 0.49 फीसदी औंधकर 129820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 325 रुपये या 0.31 फीसदी घटकर 104080 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 39 रुपये या 0.3 फीसदी घटकर 13043 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी दिसंबर वायदा 127974 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 128328 रुपये और नीचे में 126900 रुपये पर पहुंचकर, 507 रुपये या 0.4 फीसदी घटकर 127467 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 129283 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 129648 रुपये और नीचे में 128642 रुपये पर पहुंचकर, 129575 रुपये के पिछले बंद के सामने 594 रुपये या 0.46 फीसदी घटकर 128981 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 182621 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 182887 रुपये और नीचे में 177289 रुपये पर पहुंचकर, 182352 रुपये के पिछले बंद के सामने 2704 रुपये या 1.48 फीसदी औंधकर 179648 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 2625 रुपये या 1.43 फीसदी घटकर 180363 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 2717 रुपये या 1.48 फीसदी की गिरावट के साथ 180308 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। मेटल वर्ग में 3976.11 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 4.45 रुपये या 0.41 फीसदी घटकर 1072.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 2 रुपये या 0.65 फीसदी लुढ़ककर 307 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.5 रुपये या 0.54 फीसदी औंधकर 276.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 45 पैसे या 0.25 फीसदी की नरमी के साथ 182.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4227.33 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5370 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5372 रुपये और नीचे में 5331 रुपये पर पहुंचकर, 18 रुपये या 0.34 फीसदी घटकर 5338 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 18 रुपये या 0.34 फीसदी लुढ़ककर 5338 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 450.8 रुपये के भाव पर खूलकर, 455.6 रुपये के दिन के उच्च और 447.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 450 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.4 रुपये या 0.31 फीसदी लुढ़ककर 448.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 1 रुपये या 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 449 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 892.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 80 पैसे या 0.09 फीसदी के सुधार के साथ 904 रुपये प्रति किलो बोला गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11355.88 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 14529.27 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3241.46 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 297.07 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 18.44 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 418.60 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 370.55 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3841.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.19 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 14430 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 64312 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20319 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 331231 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 31577 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 18630 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 42931 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 121193 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16170 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35980 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 31337 पॉइंट पर खूलकर, 31337 के उच्च और 30932 के नीचले स्तर को छूकर, 274 पॉइंट घटकर 31070 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 14.9 रुपये की गिरावट के साथ 91.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की गिरावट के साथ 24.7 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 136000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 154 रुपये की गिरावट के साथ 861 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 185000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1506.5 रुपये की गिरावट के साथ 5018.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1080 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.35 रुपये की गिरावट के साथ 21.84 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.02 रुपये की गिरावट के साथ 2.64 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 1.4 रुपये की गिरावट के साथ 103.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 20 पैसे के सुधार के साथ 25.95 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 22 रुपये की बढ़त के साथ 254 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 243 रुपये की बढ़त के साथ 1663.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 295 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 20 पैसे के सुधार के साथ 0.9 रुपये हुआ।

विरार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य के चलते लोकल सेवा में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा विरार – दहानू रोड खंड के बीच तीसरी और चौथी लाइन परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों के तहत विरार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 3ए का विस्तार और नए होम प्लेटफॉर्म 5ए का निर्माण किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये कार्य स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में बढ़ते रेल यातायात के सुचारू संचालन में सहायक होंगे। इन कार्यों के कारण पश्चिम रेलवे की निम्नलिखित लोकल सेवा में तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक बदलाव किया जा रहा हैः

1.दादर से 10:55 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 92083 दादर – विरार लोकल अब वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी।

2.विरार से 12:10 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 92100 विरार – दादर लोकल अब वसई रोड से 12:20 बजे प्रारंभ होगी।

इसके अतिरिक्त, अगली सूचना तक विरार स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3ए पर कोई भी ट्रेन सेवा संचालित नहीं की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस परिचालन परिवर्तन पर ध्यान दें।

तत्काल बुकिंग प्रणाली में बदलावः अहमदाबाद मण्डल से चलने वाली और चार प्रतिष्ठित ट्रेनों के लिए OTP प्रमाणीकरण 5 दिसंबर से लागू

(जीएनएस)।पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो यात्री द्वारा बुकिंग के समय दिया जाएगा। ओटीपी का सफल सत्यापन होने पर ही टिकट जारी किया जाएगा।

यह OTP-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 05 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित ट्रेनों पर लागू हो जाएगी

1. ट्रेन संख्या 12957 साबरमती-नई दिल्ली स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 12297 अहमदाबाद-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 12462 साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 12268/12267 हापा–मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
5. ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी (01.12.2025 से लागू)

नई प्रणाली कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के समय वैध मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएँ, ताकि OTP सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

5 और 6 दिसंबर को साबरमती-खोडियार के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 (त्रागढ रोड फाटक) बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के साबरमती-खोडियार स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 किमी 773/4-6 (त्रागढ़ रोड फाटक) 05 दिसंबर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से 06 दिसंबर, 2025 को सायः 20.00 बजे तक ओवरहॉलिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु बंद रहेगा

सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेलवे क्रॉसिंग नंबर 241 अंडरपास वाया गोदरेज गार्डन सिटी और एस. जी. हाईवे से आवागमन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ के धोरडो से रणोत्सव 2025-26 का शुभारंभ कराया

धोरडो में रणोत्सव में 'एकत्व – एक देश, एस गीत, एक भावना' की संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ

मुख्यमंत्री ने कच्छ के पर्यटन को गति देने के लिए लखपत किलो, तेरा हेरिटेज विलेज तथा धोरडो के 179 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा शिलान्यास किया

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुआ रणोत्सव आर्थिक-सामाजिक विकास का श्रेष्ठ उदाहरण तथा ग्लोबल इवेंट बना है
- समाज, संस्कृति एवं समृद्धि के संगम से रचा गया 'धोरडो मॉडल' विश्वभर के विशेषज्ञों के लिए एक केस स्टडी
- रणोत्सव में परंपरागत कच्छी भूंगा तथा आधुनिक टैंट सिटी से प्रधानमंत्री का 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार हुआ
- रणोत्सव में पर्यटकों की सुविधा के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की राज्य सरकार की मंशा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को सफेद रेगिस्तान धोरडो से कच्छ रणोत्सव 2025 का शुभारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कच्छ के रण (रेगिस्तान) को पर्यटन का तोरण (वंदनवार) और विश्व के लिए फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सपना साकार हुआ है। इस संदर्भ में श्री पटेल ने जोड़ा कि रणोत्सव अब ग्लोबल इवेंट बन गया है और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से समाज, संस्कृति एवं समृद्धि के संगम से रचा गया धोरडो मॉडल विश्वभर के विशेषज्ञों के लिए केस स्टडी बना है।

मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने के अवसर को जोड़ने वाले 'एकत्व – एक देश, एक गीत, एक भावना' थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों, कच्छी कला तथा गुजरात की संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रणोत्सव का उद्घाटन किया।

उन्होंने कच्छ के पर्यटन को गति देने के लिए लखपत किला, तेरा हेरिटेज विला और धोरडो के 179 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा उपस्थित थे।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने रणोत्सव की शुरुआत कराते हुए कहा था, 'एक दिन दुनियाभर से पर्यटक धोरडो आएँगे और कच्छ की संस्कृति को आनंद उठाएंगे।' प्रधानमंत्री का बात सत्य सिद्ध हुई है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (डब्लूएनटीओ) ने धोरडो को 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' के अवॉर्ड से नवाजा है। कच्छी भूंगा (झोंपड़ी) और कच्छ की विविधतापूर्ण लोक संस्कृति के साथ आधुनिक सुविधा से युक्त टैंट सिटी से प्रधानमंत्री का 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार हुआ है।

कच्छ रणोत्सव से गुजरात के पर्यटन उद्योग को गति मिलने के साथ रणोत्सव को अनेक लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बताते हुए श्री पटेल ने कहा कि रणोत्सव में लाखों सैलानियों के आने के कारण परंपरागत कलाकृतियों को वैश्विक बाजार मिलने के साथ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्थानीय हस्तकला कारीगरी की वस्तुओं और 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'लोकल फॉर ग्लोबल' को वेग मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत तथा देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया है। पर्यटन के विकास के लिए कच्छ सहित समग्र गुजरात में उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और उसका लाभ पर्यटन गतिविधियों तथा विशेषकर रणोत्सव को मिल रहा है। श्री पटेल ने पर्यटकों की सुविधा के लिए और अधिक से अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की राज्य सरकार की मंशा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि सफेद रण तक पर्यटक सरलता से पहुँच सकें; इसके लिए उत्तम सड़क मार्ग, बस कनेक्टिविटी, भुज तक रेल एवं एयर कनेक्टिविटी, भुज तक रेल एवं एयर कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री के विजन से मिली है। इससे पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। गत रणोत्सव में 10 लाख से अधिक पर्यटकों ने सफेद रेगिस्तान का आनंद उठाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर नागरिकों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने इस संकल्प को साकार करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को अग्रसर बनाकर विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। धोरडो में मुख्यमंत्री ने सफेद रण की सैर करते हुए रेगिस्तान के सौंदर्य से युक्त सूर्यास्त का नजारा देखा। श्री पटेल ने धोरडो में सरदार वल्लभभाई पटेल के अखंड भारत, एक भारत के विजन को जन-जन तक पहुँचाने की भावना को चरितार्थ करने वाले सरदार स्मृतिवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति हुई।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जनकसिंह जाडेजा, विधायक सर्वश्री केशूभाई पटेल, प्रद्युमनसिंह जाडेजा, अनिरुद्धभाई दवे, पर्यनट विभाग के सचिव श्री राजेन्द्र कुमार, कच्छ जिला कलेक्टर श्री आनंद पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री उत्सव गौतम, जीएलपीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुधीर पटेल, गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) के प्रबंध निदेशक श्री प्रभव जोशी, अग्रणी श्री देवाभाई देवजीभाई वरचंद, धोरडो ग्राम पंचायत के सरपंच श्री मियाँ हुसैन सहित पदाधिकारी तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब में कल 'रेल रोको' आंदोलन, 19 जिलों में रेलवे ट्रैक पर धरना, यात्रियों को हो सकती है बड़ी परेशानी

(जीएनएस)। चंडीगढ़। पंजाब में किसानों और मजदूर संगठनों द्वारा राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में शुक्रवार, 5 दिसंबर को व्यापक 'रेल रोको' आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने ऐलान किया है कि यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पंजाब के 19 जिलों के 26 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और क्रॉसिंगों पर किया जाएगा। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला, संगरूर, फाजिल्का, मोगा, बठिंडा, मुक्तसर, मालेरकोटला, मनसा, लुधियाना, फरीदकोट और रोपड़ में यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। किसानों का कहना है कि यह आंदोलन बिजली संशोधन बिल-2025 के मसौदे को रद्द करने, प्रीपेड बिजली मीटर हटाने, पुरानी मीटर प्रणाली बहाल करने और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। किसान संगठन का आरोप है कि सरकार लगातार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है और उन्हें मजबूरन यह रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

केएमएम के वरिष्ठ नेता सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में यह आंदोलन दो घंटे का प्रतीकात्मक धरना है, लेकिन इसका असर राज्यभर में रेल यातायात पर व्यापक रूप से पड़ने की संभावना है। किसान यूनियन नेताओं का कहना है कि यह चेतावनी स्वरूप प्रदर्शन है और अगर सरकार उनकी मांगों को समय रहते नहीं सुनेगी, तो अगला कदम अनिश्चितकालीन धरना और बड़े पैमाने पर चक्का जाम हो सकता है।

किसान संगठनों का कहना है कि बिजली संशोधन विधेयक किसानों के लिए भारी आर्थिक बोझ और निजीकरण का जरिया बन सकता है। उन्होंने प्रीपेड मीटर और नई मीटर व्यवस्था को अपनाने से लागत बढ़ने और बिजली पर नियंत्रण कम होने की चिंता जताई है। इस आंदोलन में पंजाब भर के कई किसान और मजदूर संगठन शामिल हैं, जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेल ट्रैक पर उतरेंगे। रेल रोको आंदोलन के चलते राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को आगाह किया है कि वे अपनी यात्रा योजना में बदलाव करें। रेल अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और यातायात प्रभावित होने पर यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस और रोड मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। इसके बावजूद, किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन सरकार की उपेक्षा की स्थिति में उनका प्रदर्शन और अधिक सख्त रूप ले सकता है।

यह आंदोलन इस महीने के लिए केएमएम द्वारा घोषित बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिजली संशोधन बिल और अन्य नीतियों के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाना है। किसान संगठनों का कहना है कि उनकी मांगें कानूनी और संवैधानिक हैं और उनका उद्देश्य केवल किसानों के हितों की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना है।

फेसबुकिया दोस्त ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर FIR दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

(जीएनएस)। शिमला। शिमला जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में फेसबुक पर दोस्ती के जरिए एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी युवक राहुल (जुब्बल, शिमला) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, 18 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि लगभग 3-4 साल पहले उसकी फेसबुक पर राहुल से पहचान हुई थी। शुरुआत में बातचीत में दोस्ती बढ़ी और उन्होंने मोबाइल नंबर साझा किए। शिकायतकर्ता ने बताया कि राहुल ने धीरे-धीरे उसे मिलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।

पीड़िता ने कहा कि 8 अप्रैल 2025 को वह राहुल से रामपुर में मिली। आरोप है कि राहुल ने उसे जबरन अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद युवती गर्भवती हो गई, और उसके बाद आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस घटना ने न केवल पीड़िता के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि स्थानीय समुदाय में भी आक्रोश और चिंता पैदा की है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2), 64(1) और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच तेजी से चल रही है और मेडिकल परीक्षण, कानूनी प्रक्रियाओं के साथ-साथ डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसे कानून के तहत सख्त सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मामलों में परिवार और समाज की संवेदनशीलता भी जरूरी है, ताकि नाबालिगों को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस घटना ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता और कानून की पूरी कार्रवाई नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

नोएडा में सौतेले पिता ने मासूमों को नाले में फेंका, राहगीरों की बहादुरी से बचीं जानें

(जीएनएस)। नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जब एक सौतेले पिता ने अपने दो मासूम बच्चों को हत्या के इरादे से गहरे नाले में फेंक दिया। बच्चों की जान गनीमत रही कि उसी समय दो राहगीर, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, वहां से गुजर रहे थे और बच्चों की रोने की आवाज सुनकर तुरंत मदद के लिए आगे आए। कड़ाके की ठंड में दलदल और पानी में फंसे बच्चों को उन्होंने जोखिम उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला।

बचाए गए बच्चों में ढाई वर्ष की नित्तर और साढ़े तीन साल का कलू शामिल हैं। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले सोमबीर सिंह और उनके साथी दीनबंधु पारस ने बच्चों के सौतेले पिता के खिलाफ थाना सेक्टर 142 में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सेक्टर 142 के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती रात करीब 9 बजे राहगीर टियेरा सोसाइटी के पास चौहान मार्केट तिराहे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने नाले से बच्चों की आवाज सुनी। दलदल और ठंडे पानी में फंसे बच्चों को उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला।

बचाए गए बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। शुरुआती पूछताछ में बच्चों ने स्पष्ट किया कि उनके पिता आशीष ने जान से मारने की नियत से उन्हें नाले में फेंका था। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के अन्य आपराधिक नेटवर्क की संभावना भी तलाश रही है।

इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिलाया कि मानवीय साहस और तत्परता किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी की जान बचा सकती है। राहगीरों की त्वरित कार्रवाई और जोखिम उठाकर बच्चों को बचाना स्थानीय समुदाय के लिए मिसाल बन गया है।

देवरिया में अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलने वाला साइबर गिरोह धराया, सिमबॉक्स और एंटीना समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद

(जीएनएस)। देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में साइबर क्राइम, एसओजी और बीएसएनएल की संयुक्त टीम ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय कॉल धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह विदेशी कॉल को लोकल कॉल में बदलकर अवैध आर्थिक लाभ कमाने का जाल बिछा रहा था। कार्रवाई में गिरोह के सरगना तेज नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया और सिमबॉक्स, सैकड़ों सिम कार्ड, एंटिना, लैपटॉप, राउटर सहित भारी मात्रा में उपकरण जब्त किए गए।

मुखबिर की सूचना पर टीम ने कोतवाली क्षेत्र के रामगुलाम टोला में छापेमारी की। पूछताछ में तेज नारायण सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 से 2022 तक मॉरिशस में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्य करते समय उसकी मुलाकात दो बांग्लादेशी नागरिकों आदिल अहमद और समीर से हुई। वहीं से उसे अंतरराष्ट्रीय VOIP कॉल को लोकल कॉल में बदलने की तकनीक सीखने को मिली। भारत लौटने के बाद वह कोलकाता गया और वहां से सिमबॉक्स और भारतीय सिम कार्ड लेकर घर पर नेटवर्क तैयार कर अवैध कॉलिंग गतिविधियां शुरू कर दी।

अभियुक्त ने खुलासा किया कि समीर उसे व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक और लॉगिन विवरण भेजता था। लिंक पर लॉगिन करने से सिमबॉक्स में लगे सिम सक्रिय हो जाते और अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में परिवर्तित कर दिया जाता। इससे दूरसंचार विभाग और सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान होता था।

छापेमारी में टीम ने 6 सिमबॉक्स, 6 वाई-फाई राउटर, 43 बड़े और 169 छोटे एंटिना, 219 बीएसएनएल सिम कार्ड, कई केबल, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 2 बैंक पासबुक, 9 चेकबुक, 11 एटीएम कार्ड और अन्य उपकरण जब्त किए। गिरोह ने अपने नेटवर्क को 212 छोटे-बड़े एंटिना से फैला रखा था, जिससे अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलना संभव हो रहा था।

थाना साइबर क्राइम देवरिया में मामला मु0अ0सं0 18/2025 के तहत दर्ज किया गया है। इसमें धारा 318(4), 319(2), 340(2) बीएनएस, भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम 1933, दूरसंचार अधिनियम और आईटी एक्ट 66C, 66D के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी और छापेमारी में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार, उ0नि0 विनायक सिंह, उ0नि0 विनय सिंह, साइबर टीम, एसओजी और बीएसएनएल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस मामले से स्पष्ट हो गया कि आधुनिक तकनीक का गलत इस्तेमाल किस तरह से बड़े पैमाने पर वित्तीय और दूरसंचार प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्य भी जल्द पकड़े जाएंगे और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा, जिससे राज्य और देश में इस तरह की अवैध कॉलिंग गतिविधियों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में एक नागरिक की मौत, बीएसएफ ने उठाया कड़ा कदम

(जीएनएस)। कूचबिहार। भारत–बांग्लादेश सीमा के माथाभंगा–1 ब्लॉक में बुधवार देर रात हुई एक गंभीर घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। घटना बैरागीहाट ग्राम पंचायत के चेना काटा इलाके में हुई, जहां एक बांग्लादेशी नागरिक सीमा पार कर अवैध तस्करी में लिप्त था। सुरक्षा बलों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पलटकर हमला किया, जिससे बीएसएफ को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से बांग्लादेश के पाटग्राम निवासी मोहम्मद सबूज हसन (30) गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें माथाभंगा महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तन्मय मुखर्जी ने बताया कि घटना रात ढाई बजे हुई और सुरक्षा बल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा नियमों के अनुरूप थी। उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामले की पूरी जांच चल रही है। थाना माथाभंगा की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतक युवक तारबंदी पार कर तस्करी करने की कोशिश में लगा था। बीएसएफ जवानों ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने पलटकर हमला किया। सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को रोका, लेकिन युवक की मौत ने सीमा क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की गंभीरता को उजागर किया। सुरक्षा बलों के अनुसार, यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत–बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीएसएफ ने इलाके में पैट्रोलिंग बढ़ा दी है और निगरानी को और भी सख्त किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हाईटेक निगरानी उपकरणों, ड्रोन और गश्त दलों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इस घटना ने यह भी साफ किया कि सीमा पर तैनात जवान न केवल देश की सुरक्षा के लिए लगातार सतर्क हैं, बल्कि उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सही समय पर की गई कार्रवाई न केवल अवैध गतिविधियों को रोकती है, बल्कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में भी मदद करती है।

घटना ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को भी उजागर किया है। बीएसएफ और पुलिस अधिकारी मिलकर निगरानी बढ़ा रहे हैं और किसी भी संभावित तस्करी या घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मदार-पालनपुर सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के मदार-पालनपुर सेक्शन के सोमेसर और जवाली स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 613 किमी 464/7-8 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग हेतु ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त तथा कुछ ट्रेनें डायवर्ट एवं रिशेड्यूल रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

निरस्त ट्रेन

▸▸05 और 6 दिसंबर 2025 को साबरमती से चलने वाली ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधुपर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

▸▸04 और 5 दिसंबर 2025 को जोधपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

▸▸4 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 20943 बांद्रा टर्मिनस – भगतकी कोठी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा - पालनपुर - मारवाड़ जं. - लूनी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-पाटन-भीलड़ी-समदड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन को भीलड़ी,मारवाड़ भीनवाल-जालोर-समदड़ी-लूनी स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

▸▸5 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 20944 भगतकी कोठी - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग लूनी-मारवाड़ जं.- पालनपुर - महेसाणा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया लूनी-समदड़ी-भीलड़ी-पाटन - महेसाणा के रास्ते चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन को भीलड़ी,मारवाड़ भीनवाल-जालोर-समदड़ी-लूनी स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

▸▸5 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 20946 हड़पसर - जोधपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा -पालनपुर - मारवाड़ जं. - लूनी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-पाटन-भीलड़ी-समदड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन को भीलड़ी,मारवाड़ भीनवाल-जालोर-समदड़ी-लूनी स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

रिशेड्यूल ट्रेनें

▸▸05 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस साबरमती से 3.15 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

▸▸05 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19031 साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस साबरमती से 2.15 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

▸▸04 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस श्री गंगानगर से 6.00 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

▸▸05 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस हनुमानगढ़ से 3.00 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना, मार्ग और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

आगामी VGRC, राजकोट में विश्व मंच पर चमकेगी टंगालिया हस्तकला की पहचान, टंगालिया कारीगरों की कला और उपलब्धियाँ होंगी प्रमुख आकर्षण

टंगालिया हस्तकला के माध्यम से पद्मश्री लवजीभाई परमार गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर को दे रहे नई शक्ति

(जीएनएस)। गांधीनगर : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र "हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी" से प्रेरित होकर राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों को व्यापक मंच पर प्रदर्शित करेगा। टंगालिया कला, गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी हस्तकरघा परंपरा है, जो अपने दानेदार पैटर्न के लिए जानी जाती है। सुरेंद्रनगर के डांगासिया समुदाय के कारीगर इस कला को आज भी बेहद निपुणता से संरक्षित किए हुए हैं। इसमें अतिरिक्त वेफ्ट धागों को वार्प धागों पर बारीकी से लपेटकर सुंदर ज्यामितीय डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसकी अनोखी तकनीक और सांस्कृतिक महत्व के कारण टंगालिया को भौगोलिक संकेत (GI) का भी दर्जा मिला है, जो इसकी विशिष्टता और परंपरा की रक्षा करता है।

कभी विलुप्त के कगार पर पहुँच चुकी यह प्राचीन कला आज फिर नई पहचान बना रही है। आज बदलते समय में दुनिया में पुरातन, हस्त निर्मित और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी वस्तुओं की बढ़ती मांग ने इसे दोबारा जीवंत कर दिया। आज हस्त निर्मित उत्पादों की वैश्विक लोकप्रियता के चलते गुजरात के टंगालिया कारीगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। इस पुनर्जीवन के प्रमुख सूत्रधार हैं लवजीभाई परमार, जो पारंपरिक टंगालिया बुनाई के माहिर कलाकार हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में उनके योगदान को मान देते हुए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।

लवजीभाई परमार पिछले चार दशकों से इस प्राचीन कला के संरक्षण और संवर्धन में जुटे हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया है जहाँ युवा कारीगरों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाज़ार से जुड़ने में मदद मिलती है। देशभर में प्रदर्शनियाँ आयोजित कर और विभिन्न विक्रेताओं से जुड़कर उन्होंने इस कला में नई ऊर्जा भर दी। इसी कारण उन्हें "टंगालियानो त्राणहार" यानी टंगालिया कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है।

टंगालिया कला की वैश्विक लोकप्रियता का एक उदाहरण सुरेंद्रनगर के कारीगर बलदेव मोहनभाई राठौड़ हैं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म "F1" के लिए अभिनेता ब्रैड पिट द्वारा पहनी गई टंगालिया शर्ट तैयार की थी। यह उपलब्धि गुजरात की इस प्राचीन कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण क्षण बनी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शक मंत्र "विकास भी, विरासत भी" को साकार करने में टंगालिया बुनाई की यह परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गुजरात की सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक गौरव का मजबूत प्रतीक है।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इस सहयोग को और आगे बढ़ाएगी। इसमें संयुक्त उद्यमों, कौशल विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए अवसर मिलेंगे। कच्छ और सौराष्ट्र को विशेष महत्व देने से स्पष्ट होता है कि सरकार के लिए औद्योगिक विकास के साथ-साथ सामुदायिक सशक्तीकरण, कौशल उन्नयन और पारंपरिक आजीविकाओं का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेन्स वैश्विक निवेशकों, स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर लाएगी। यह आयोजन गुजरात की आर्थिक शक्ति और उसकी सांस्कृतिक जड़ों, दोनों का उत्सव बनेगा। इसका संदेश साफ होगा कि विकास तभी सार्थक है जब वह समुदायों को आगे बढ़ाए, विरासत को सुरक्षित रखे और लोगों में गर्व की भावना पैदा करे।